

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2018 एल.आर. एक्ट

आनन्द सिंह पुत्र धौकल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा
तहसील व जिला चूरु राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. मु. मैन कंवर पत्नी लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम
श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
2. विजय सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा
तहसील व जिला चूरु।
3. लीलू सिंह पुत्र लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा
तहसील व जिला चूरु।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु जिला चूरु
5. बैंक ऑफ बड़ोदा जरिये शाखा प्रबन्धक रतननगर तहसील व जिला
चूरु

रेस्पोडेन्टस

6. मदन कंवर पत्नी धौकल सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
7. सदा कंवर पुत्री धौकल सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
8. प्रेम कंवर पुत्री धौकल सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
9. बलवीर सिंह पुत्र धौकल सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
10. विक्रम सिंह पुत्र धौकल सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
11. मंजू कंवर पत्नी रणवीर सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।
12. विवेक पुत्र रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी
ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरु।

आदेश दिनांक
14.8.19 द्वारा नाम
हटाया गया

गौण रेस्पोडेन्टस


उपस्थित :- श्री रोशन अली - अभिभाषक अपीलांट
श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित - रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3
श्री सुभाष सहू - राजकीय अभिभाषक


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 31-10-2019

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चूरु के निर्णय दिनांक 15-05-2017 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं गौण रेस्पोंडेन्ट्स की कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 201 व 215 वाके रोहि ग्राम श्यामपुरा तहसील चूरु में स्थित है। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी सीव सरकाकर उनकी 3-4 बीघा भूमि अपने कब्जे में ले रखी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीमाज्ञान व पत्थर गढ़ी करने के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध अपीलान्त ने यह अपील पेश की है।
3. उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये तथा बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित उपस्थित नहीं आये।
4. अपीलान्त के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलार्थी एवं गौण रेस्पोंडेन्ट्स की कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 201 व 215 वाके रोहि ग्राम श्यामपुरा तहसील चूरु में स्थित है। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी सीव सरकाकर उनकी 3-4 बीघा भूमि अपने कब्जे में ले रखी है। ऐसे में रेस्पोंडेन्ट द्वारा धारा 183 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी। धारा 111 व 128 काश्तकारी अधिनियम में किसी प्रकार की कार्यवाही करने के अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी


उपस्थित अधिकारी
बीकानेर

व रेस्पोजेन्ट के खेत के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से करीब 20 वर्षों पूर्व पत्थर की पट्टीया लगाकर तारबन्दी की हुई है। हमारी 6 बीघा भूमि पहले से ही कम है। विभाजन का दावा उपखण्ड अधिकारी चूरु में चल रहा है। दावे के निर्णय अनुसार आगे कार्यवाही हो जायेगी। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.5.17 को पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी करने गया तो बताया गया कि अभी लोक अदालत के केम्प चल रहे हैं तारीख पेशीया तह कर रहे हैं। तत्पश्चात दिनांक 29.1.18 को पत्रावली में फैसला होना बताया गया। अतः अपीलान्त की अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील स्वीकार करते हुवे उपखण्ड अधिकारी चूरु का आदेश दिनांक 15.5.17 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही हैं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपीलांत का मुख्य कथन है कि इसी भूमि से संबन्धित एक दावा अलग से विचाराधीन होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के तहत अलग से कार्यवाही नहीं हो सकती।

अपील पेश करने में हुये विलम्ब के बारे में बताये गये कारण संतोषजनक पाये जाने पर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलाधीन आदेश राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में भिन्नता की जानकारी होने पर किसी एक पक्षकार की दरखास्त पर सीमाज्ञान

एव पत्थर गढ़ी करवाने के लिये जारी किया गया है। भूमि के सीमा विवादों में रिकार्ड व मौके की स्थिति की पैमाइश करना तथा उक्त पैमाइश के आधार पर पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करना भू अभिलेख


अधिकारी का दायित्व है। यदि किसी पक्षकार की सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आपत्ति हो तो सीमांकन करने वाले अधिकारी के

समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस आड़ में कार्यवाही शुरू करने की उसकी वैधानिकता को चुनौति नहीं दी जा सकती। सीमा विवाद


सुभागाय आहुत
बीकानेर

तथा अतिक्रमण के मामलों के निस्तारण से पूर्व सीमांकन किया जाना आवश्यक है। यदि किसी पक्षकार के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो भी सीमा ज्ञान तथा पत्थर गढ़ी की कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं है।

लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31--10--2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

